जे० डी० एफ०) का सृजन वर्ष 1986-87 में किया गया था । विशेष पटसन विकास निधि के कार्यान्वयन की प्रगति निम्नानुसार है :—

योजना का नाम	आवंटन (रु० करोड़)	रिलीज (रु० करोड़)
1	2	3
1. पटसन कृषि विकास कार्यक्रम	25.00	18.00
2. गोदामों और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिये भारतीय पटसन निगम को सहायता ।	10.00	2.00
3. उत्पाद विविधीकरण और अनुसंधान एवं विकास सहायता ।	10.00	8.35
4. पटसन उद्योग में कामगारों के लाभ के लिये योजनाएं :		
(क) श्रमिकों का पुनर्वासन	10.00	--
(ख) आधुनिकीकरण से जुड़ा श्रमिक पुनर्वासन	22.50	--
(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपनाने वाली मिलों के कामगारों की भविष्य निधि/ई० एस० आई० के बकाया का आंशिक भुगतान ।	16.00	4.67
(घ) फ़ालतू कामगारों के लिये प्रशिक्षण और बैंक वित्त ।	5.00	--
	98.50	33.02
अर्थात्	100.00	

सरकार ने अभी हाल ही में विशेष पटसन विकास निधि के लोचशील पुनः नियोजन की अनुमति प्रदान की है ताकि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं को और अधिक व्यावहारिक और मौलिक आवश्यकताओं के उन्मुख बनाया जा सके ।

(घ) और (ङ) सरकार ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना की थी जिसने सिफारिश की है कि पटसन क्षेत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि विविधीकृत अन्त प्रयोगों में फाईबर के रूप में पटसन की पूरी संभाव्यता को मान्यता दी जाए। इस लिए पटसन क्षेत्र के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह पटसन उपजाने वाले किसानों, मिल के कामगारों तथा इस फाइबर से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के हितों के लिए पुनर्निर्माण कार्य शुरू करें । इस प्रकार के विविधीकरण से पटसन उद्योग की मूल्य वसूली में वृद्धि होगी और इसके फलस्वरूप पटसन फाइबर के लिए मांग बढ़ेगी जिससे किसानों को उपज के लिए और अधिक लाभप्रद कीमतें वसूल करने में सहायता मिलेगी। समिति ने सिफारिश की है कि विविधीकरण बढ़ाने के लिए मार्जिन धनराशि की सहायता दी जाए तथा सभी सम्बद्ध क्षेत्रों में सुचारू प्रबंध किए जायें ।

हथकरघा उद्योग का विकास

2605. श्रीमती सुषमा स्वराज :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा विकास आयुक्त ने गत वर्षों के दौरान हथकरघा उद्योग के विकास के लिए विभिन्न योजनायें लागू की हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि हथकरघा क्षेत्र की उत्पादकता बढाने और तैयार माल को लाभकारी मूल्य पर बेचने के लिए कुछ योजनायें बनाई गई हैं,

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान हथकरघा उद्योग की उत्पादकता बढ़ाने और उनके उत्पादों की बिक्री उचित मूल्य पर करने की व्यवस्था करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) हथकरघों पर उत्पादन में वृद्धि करने और तैयार माल उचित मूल्यों पर विक्रय करने में सहयोग देने हेतु हथकरघा क्षेत्र में कार्यान्वित योजनाओं में से कुछ योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) करघों के आधुनिकीकरण/नवीनीकरण/खरीद के लिए सहायता ।

(2) बुनकर सेवा केन्द्रों के माध्यम से बुनकरों का प्रशिक्षण ।

(3) विपणन विकास सहायता योजना ।

(4) राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपों में हथकरघा उत्पादों की बिक्री पर विशेष छूट ।

(5) विपणन काम्पलैक्स की स्थापना के लिए सहायता ।

(6) राष्ट्रीय डिज़ाइन संग्रह कार्यक्रम ।

(7) प्रोजेक्ट पैकेज योजना ।

(घ) व (ङ) यद्यपि उत्पादन और हथकरघा उत्पादों की बिक्री के संदर्भ में विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं लेकिन आठवीं योजना के दौरान प्लान योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है ।

हथकरघा की उत्पादकता

2606. श्री वीरेन जे० शाह :
श्री राम जेठमलानी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 सितम्बर, 1992 के "आब्जरवर" में "हैंडलूम वीवरस् गेट टू बेनीफिट फ्राम ग्रांट्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या यह सच है कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर हथकरघा की उत्पादकता प्रति हथकरघा 5.12 मीटर है,

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है,

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली राज्य में यह उत्पादकता प्रति हथकरघा 14.26 मीटर है जबकि असम राज्य में यह उत्पादकता प्रति हथकरघा केवल 0.63 मीटर है,

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस विषमता को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, और